हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 25 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–40/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 19) जो आज दिनांक 25 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

———————

2011 का विधेयक संख्यांक 19

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.–**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 5 का संशोधन.–**हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः–

''(ज) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित भूमि जो,–

(i) औद्योगिक इकाई(यों) या जलविद्युत परियोजना(ओं) या पर्यटन इकाई(यों) या सूचना प्रौद्योगिकी स्थल(लों) या बॉयो–तकनीकी स्थल(लों) को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित किसी कम्पनी;

(ii) जातिवाद, मदात्यय और नशीली दवाओं के व्यसन आदि के उन्मूलन सहित नैतिक या धर्म–निरपेक्ष शिक्षाओं का प्रचार करने वाले धार्मिक या अध्यात्मिक निकायों या संगठनों या संपर्वतकों; और

(iii) शैक्षिक और खेल प्रसुविधाओं तथा अवसंरचना का सृजन करने और अनुरक्षण के लिए निकायों या संगठनों;

द्वारा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के वास्तविक उपयोग के लिए, धारित है या किसी भी रीति में धारित की जानी है। यह विचार करते समय कि क्या ऐसी भूमि इस प्रकार धारित है या अर्जित की जानी है राज्य सरकार, पूर्व धारित भूमि जिसके अन्तर्गत पूर्वोक्त प्रयोजनों के उपयोग हेतु पहले से धारित भूमि भी होगी, की सीमा और अवस्थिति यदि कोई हो, और इसके भविष्य के विस्तारण के लिए उपयुक्त आवश्यकता का ध्यान भी रखेगीः

परन्तु यदि राज्य सरकार का, इस खण्ड के अधीन अधिसूचित भूमि की दशा में, समाधान हो जाता है कि भूमि वास्तव में अर्जित नहीं की गई है या उस प्रयोजन के लिए वास्तविक उपयोग में नहीं लाई गई है जिसके लिए, इस खण्ड के अधीन जारी की गई अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि (या पाँच वर्ष से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि जैसी राज्य सरकार विनिश्चित करे) के भीतर यह भूमि अर्जित या धारित की जानी प्रस्तावित थी, तो राज्य सरकार ऐसी जाँच, जैसी यह उचित समझे, के पश्चात् विहित रीति में प्रकाशित आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि या उसका कोई भाग, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में उल्लिखित है, छूट प्राप्त भूमि नहीं रहेगी।''।

———

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 19 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMNT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No.19 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972, for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) land as is notified by the State Government being land which is held or to be acquired in any manner, by,-

(i) a Company incorporated under the Companies Act,1956 for the purpose of setting up of industrial unit(s) or hydel project(s) or tourism unit(s) or information technology park (s) or bio-technology park(s);

(ii) religious or spiritual bodies or organizations or promoters, propagating moral or secular teachings including eradication of casteism, alco-holism and drug addiction etc.; and

(iii) bodies or organizations for creating and maintaining educational and sports facilities and infrastructure;

for bonafide use for any of the above specified purposes. In considering whether such land is so held or to be acquired, the State Government shall have regard to the extent and location of land, if any, already held including any land which it may already hold for use for abovesaid purposes and its genuine requirement for future expansion:

Provided that if the State Government, in the case of land notified under this clause, is satisfied that the land has not been actually acquired or has not been actually put to use for the purpose for which it was proposed to be acquired or hold, within a period of two years (or such extended period not exceeding five years as the State Government may decide) from the date of notification issued under this clause, the State Government may, after making such enquiry as it thinks fit, by order published in the prescribed manner, direct that the land or any part thereof specified in the order shall, with effect from such date as is mentioned in the order, cease to be exempted land.".

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government is inviting investors and entrepreneurs in industries, information technology, bio-technology, tourism and hydel projects etc. in the interest of development of the State but they cannot hold land more than the permissible area specified under section 4 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, for the purpose of setting up of such project. Further religious and spiritual bodies and organizations promoting moral and secular teaching including eradication of casteism, alcoholism and drug addictions etc. and bodies and organizations creating educational and sports facilities and infrastructure cannot hold land more than permissible area specified under

section 4 of the Act ibid. Thus, it has been considered necessary to amend section 5 suitably and to provide exemption to these bodies etc. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(THAKUR GULAB SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The , 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—